

एक असाधारण वैश्विक राजनेता

आजाद भारत के इतिहास में पिछले साल आज का दिन एक निर्णायक मोड़ का साक्षी रहा। इस दिन नरेन्द्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने लोकसभा चुनाव में युग-परिवर्तक विजय के बाद अपना नेता चुना। प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने पहले दिन से ही प्रमाणित किया कि वे एक असाधारण वैश्विक राजनेता हैं। भारत को आधुनिक और हर तरह से मजबूत बनाने की अपनी व्यापक दृष्टि, नई सोच, बेजोड़ जीवटता, जुनून और प्रतिबद्धता तथा भारत की क्षमताओं को यथार्थ में बदलने के लिए उनके द्वारा उठाए गए सूझ-बूझ भरे कदमों ने भारत को लेकर दुनिया को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया।

मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान
के ब्लॉग से

देश को पॉलिसेी पैरालिसिस से मुक्त कराकर नरेन्द्र मोदी ने हर लिहाज से एक साफ-सुथरी सक्षम और गतिशील सरकार दी, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित और कार्य-कुशल है। सरकार चलाने के पुराने पड़ चुके और जड़ता की हद तक पहुंच चुके ढर्रे को बदलने के लिए प्रतिबद्ध श्री मोदी ने एक नई कार्य-संस्कृति विकसित की, जिसमें लाल फीताशाही और

प्रशासनिक क्लिष्टता नहीं है।

अपनी प्रासंगिकता खो चुके योजना आयोग की जगह उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति) का गठन किया। इससे तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश और संदर्भ के अनुरूप भारत की नीतियों और उन्हें लागू करने के तौर-तरीके में प्रभावी बदलाव लाया जा सके। यह कदम भी उनकी मौलिक सोच का ही परिणाम है। नीति आयोग के गठन से राज्यों को अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों और सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के साथ-साथ धनराशि खर्च करने की स्वतंत्रता भी मिली है। श्री मोदी ने समय-समय पर विभिन्न मंचों से यह बात बहुत जोर देकर कही है कि भारत की शक्ति उसके राज्यों में निहित है। अपनी इसी सोच के अनुरूप उन्होंने केन्द्रीय करों के विभाजनीय पूल में से 32 की जगह 42 प्रतिशत राशि राज्यों को देने का क्रांतिकारी कदम उठाया। एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता होने के नाते उन्होंने ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सभी राजनीतिक विचारधारा के नेता देश के विकास को लेकर एकमत और एकजुट हों। वे टीम इंडिया के पक्षधर हैं, जिसमें सभी राजनीतिक धाराओं के नेता वैचारिक मतभेद भुलाकर भारत के विकास के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग की परिषद में शामिल किया है। वे राज्यों के बीच विकास के मामलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के पक्षधर हैं। इससे भारत का समग्र विकास होगा। बहुत लम्बे समय के बाद भारत को एक ऐसा वैश्विक नेता मिला है, जिनकी दृष्टि उदार है और जो दूसरे के मतों का पूरा सम्मान करते हैं। सभी राज्यों के नेताओं को देश में चल रही बदलाव की लहर का पूरा लाभ उठाते हुए भारत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए।